दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 ‖ Email :- nyaysakshi@gmail.com ‖ रायगढ़, गुरूवार 14 फरवरी 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-01, अंक-136

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

हैती में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में छह की मौत, 78 कैदी जेल से भागे

पोर्ट ऑ प्रिंस (आरएनएस)। हैती में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे के इस्तीफे की मांग को लेकर करीब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शनों में छह कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मंगलवार को प्रदर्शनों के दौरान एच्चिन शहर की एक जेल से सभी 78 कैदी फरार हो गए। राष्ट्रीय पुलिस के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में कैदी जेल तोड़कर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब एक कैदखाने से लगे पुलिस थाने के सामने राष्ट्रपति मोइसे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे।

सहमति बनी, ट्रंप को मिलेंगे 1.4 अरब डॉलर

मेक्सिको सीमा पर दीवार

वॉशिंगटन (आरएनएस)। सरकारी कामकाज को फिर से ठप होने से बचाने और अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने को लेकर अमेरिकी सांसदों के बीच समझौता हो गया है। सोमवार की रात हुए इस समझौते के तहत राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को दीवार बनाने के लिए महज 1.4 अरब डॉलर की राशि मिलेगी। संसदीय सहयोगियों के मुताबिक, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी किसी भी सूरत में फिर से सरकारी कामकाज ठप नहीं होने देना चाहती थी। ऐसे में उन्हें दीवार बनाने के लिए मिलने वाली राशि से समझौता करना पड़ा।

मादक पदार्थों का कुख्यात तस्कर अल चापो दोषी करार

न्यूयॉर्क (आरएनएस)। मेक्सिको में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर जोआक्विन ''अल चापो'' गुजमैन को करीब 25 साल में किये गये अनेक अपराधों का दोषी ठहराया गया है। अल चापो को दुनिया के सबसे शक्तिशाली गिरोहों में से एक गिरोह के सरगना के रूप में कई अपराधों को अंजाम देने का दोषी पाया गया। कुख्यात संगठन 'सिनालोआ गिरोह' के पूर्व बॉस 61 वर्षीय अल चापो को अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

संसद में बैरिकेड से टकराई सांसद की कार

सुरक्षाकर्मियों में मचा हडकंप

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद में उस समय अफरा-तफरी का माहोल मच गया जब एक सांसद की कार संसद भवन के अंदर बैरिकेड से टकरा गई। यह कार कांग्रेस के मणिपुर से लोकसभा सांसद थोकचोम मेनिया की है। इस घटना के बाद से संसद की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षाबल घटना के पीछे के कारणों का पता लगा रही है।

250 झुग्गियों में भीषण आग, काबू पाने की कोशिश

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली के पश्चिमपुरी में 250 झुग्गियों में भीषण आग लग गई. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि झुग्गियों का काफी हिस्सा जल चुका है. जबकि कुछ हिस्से पर नियंत्रित कर लिया गया है. दमकल विभाग का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि एक के बाद एक 250 झुग्गियों को चपेट में ले लिया.

बांगो थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी पलटी, बाल-बाल बचे चालक और सिपाही

कोरबा. बांगो थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी पलट गई। इसमें चालक और सिपाही की जान बाल बची। घटना बुधवार सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है। डायल 112 की वाहन सीजी 03, 9216 को लेकर ड्राइवर सतीश कंवर और सिपाही हेमलाल कुर्रे बांगो के पास नाला किनारे जा रहे थे। ढलान पर गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इसमें सतीश और हेमलाल बाल बचे।

यूपीए की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ते में किया राफेल सौदा

कैग रिपोर्ट में मोदी सरकार को राहत

नईदिल्ली (आरएनएस)। राफेल मुद्दे पर राज्यसभा में कैग रिपोर्ट पेश हो गई है. सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की राफेल डील यूपीए सरकार में प्रस्तावित डील से सस्ती है. सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राफेल डील यूपीए से 2.86 फीसदी सस्ते में हुई है. कैग रिपोर्ट में कहा गया है, साल 2016 में मोदी सरकार की तरफ से साइन की गई राफेल फाइटर जेट डील 2007 में यूपीए सरकार की तरफ से प्रस्तावित डील की तुलना में

2.86 प्रतिशत सस्ती है.

2016 में रक्षा मंत्रालय ने कहा था राफेल सौदे की घटी हुई कीमतें 2007 की तुलना में 9 गुना कम हैं. हालांकि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राफेल के बेसिक फ्लाईवे विमान को 2007 की कीमत पर ही खरीदा गया है.

कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान में भारत की जरूरतों के मुताबिक बदलाव का खर्च 17 प्रतिशत सस्ता था. हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय वायुसेना का मानना था कि विमान में भारत के हिसाब से विशेष बदलाव की आवश्यकता नहीं थी. वहीं राफेल मुद्दे पर कांग्रेस का संसद परिसर में प्रदर्शन जारी है. राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह राफेल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए. आपको बता दें कि दोपहर 3.30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. इस बीच कांग्रेस ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की है. सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक-एनडीए का सौदा 2.86 फीसदी सस्ता है, मतलब मोदी सरकार ने यूपीए से सस्ते में राफेल खरीदा है.

बच्चे के साथ हुआ हादसा तो हो सकती है जेल

नईदिल्ली (आरएनएस)। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए मोदी सरकार बहुत जल्द स्कूल सुरक्षा नियमों में नया प्रावधान करने जा रही है. नए प्रावधान के मुताबिक स्कूल में बच्चे के साथ किसी भी तरह का हादसा होता है या फिर बच्चों की सुरक्षा में खामी पाई जाती है तो इसके लिए पूरी तरह से स्कूल प्रबंधक जिम्मेदार होंगे. यही नहीं इस लापरवाही के लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल सुरक्षा नियमों में नए प्रावधान करने जा रहा है. मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह नियम मार्च महीने में सभी स्कूलों में लागू किया जा सकता है.

स्कूल प्रशासन पर सख्त होगी मोदी सरकार

जानकारी के मुताबिक साल 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में प्रबंधकों की जवाबदेही तय किए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2018 को सरकार से छह महीने के अंदर स्कूल सुरक्षा नियम तैयार करने का आदेश दिया था. इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साल 2017 में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक मैनुअल जारी किया था.

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 304 उम्मीदवारों का नामांकनः नोबेल समिति

स्टॉकहोम (आरएनएस)। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 304 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है जो कि अब तक का चौथा सर्वाधिक नामांकन है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जारी बयान के अनुसार 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 304 उम्मीदवार हैं जिनमें से 219 व्यक्ति हैं और 85 संगठन हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 304 उम्मीदवारों का यह आंकड़ा अब तक के उम्मीदवारों की चौथी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 376 उम्मीदवारों का रिकॉर्ड 2016 में पहुंचा था। समिति ने कहा कि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की सूची का खुलासा 50 साल बाद तक नहीं किया जा सकता। समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सभी जीवित व्यक्ति और सक्रिय संगठन या संस्थान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। नोबेल फाउंडेशन के क़ानूनों द्वारा परिभाषित नामांकनों को ही वैध नामांकन माना जाता है। वैध नामांकन के लिए 31 जनवरी के पहले फॉर्म जमा किया जाना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से नामांकन के लिए अनुरोध किया जाता है।

अंतरिम बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को राज्यसभा से पारित करने पर बनी सहमति

नयी दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले सात दिनों से लगातार बाधित चल रही बैठक बुधवार को सुचारु बनाने पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बन गयी है। सदन की बैठक शुरु होने से पहले सभापति वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में आज सभी दलों के नेताओं के साथ हुयी बैठक में विपक्ष के नेताओं ने अंतरिम बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर करने पर सहमति कायम हो गयी।

सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल के अनुरोध पर विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक सुचारु बनाने पर सहमति दी। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र का आज अंतिम दिन है।

बडगाम में दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर (आरएनएस)। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन सेना को बड़ी कामयाबी मिली है. मंगलवार को पुलवामा में हिज्बुल आतंकवादी हिलाल अहमद राठेर को ढेर करने के बाद आज बडगाम में सेना ने 2 आतंकी मार गिराए हैं. एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद कर लिया गया है. मारे गए आतंकियों की

पहचान नहीं हुई है.

बुधवार सुबह सेना को बडगाम में दो आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी. जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इलाके की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई. इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी. इस मुठभेड़ के दौरान सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया.

इजरायल से मंगाए जाएंगे 54 हारोप ड्रोन

मोदी सरकार का एयरफोर्स को बड़ा तोहफा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना की मानवरहित युद्ध क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 54 इजरायली हारोप ड्रोन की खरीद को मंजूरी दे दी है. ये किलर ड्रोन दुश्मन के हाई-वैल्यू मिलिट्री टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है.

सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्रालय ने इन 54 हमलावर ड्रोनों की खरीद को मंजूरी दे दी थी. खबरों के मुताबिक ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे.

क्या है ख़ासियत?

आपको बता दें ये ड्रोन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर से लैस होते हैं. जो विस्फोट करने से पहले हाई वैल्यू वाले सैन्य ठिकानों जैसे निगरानी के ठिकाने और रडार स्टेशनों पर निगरानी भी कर सकते हैं.

जीआईपी मॉल स्थित बर्गर किंग में कार्ड क्लोन कर 50 लाख का चूना

नोएडा। जीआईपी मॉल स्थित बर्गर किंग रेस्त्रां में पेमेंट के दौरान एटीएम कार्ड क्लोन कर लेने के मामले में नए खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि अब तक करीब 500 से ज्यादा लोगों के कार्ड क्लोन कर लगभग 50 लाख रुपये खातों से निकाले जा चुके हैं।

पुलिस अब पीड़ितों की डिटेल जुटाकर इस मामले के असली मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। इस मामले में दो बैंकों के अधिकारियों ने पुलिस संपर्क कर अनुमानित रकम की जानकारी दी है। बता दें कि सोमवार को सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बर्गर किंग के सेल्स मैनेजर सुमित को गिरफ्तार कर उसके पास से एटीएम व क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाने वाली स्किमर डिवाइस बरामद की थी। यह डिवाइस उसे राहुल नामक युवक ने दी थी।

पूछताछ में सुमित ने बताया था कि वह दिसंबर 2018 से लेकर अब तक रोजाना 50- 60 लोगों के एटीएम कार्ड क्लोन कर डेटा चुरा लेता था। इसके बाद वह 10-15 हजार रुपये लेकर राहुल को वह डेटा बेच देता था।

माकपा ने लगाया कैग रिपोर्ट लीक होने का आरोप

नई दिल्ली (आरएनएस)। माकपा ने लड़ाकू विमान राफेल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के संसद में पेश होने से पहले, इसके कुछ अंश समाचार चौनलों पर प्रसारित होने पर सवाल खड़े करते हुये रिपोर्ट के लीक होने का आरोप लगाया है।

माकपा के लोकसभा सदस्य मोहम्मद सलीम ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राफेल खरीद मामले में कैग की रिपोर्ट पेश किये जाने की चर्चा थी। लेकिन यह रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि इस बीच कुछ समाचार चौनलों पर इस रिपोर्ट से जुड़ी खबरें प्रसारित की गयीं। सलीम ने कहा कि कैग रिपोर्ट सबसे पहले संसद के समक्ष पेश किया जाना संसदीय विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि संसद की पहुंच से दूर रही कैग रिपोर्ट समाचार चौनलों तक कैसे पहुंच गयी। इसका सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। सलीम ने सरकार पर आधिकारिक आंकड़ों के एकत्रीकरण और प्रकाशन की व्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार के आंकड़ों की जांच करने वाली प्राक्कलन समिति की बैठक पिछले साल अक्तूबर से ही नहीं हुयी है। बजट प्रस्ताव पर वित्त मंत्री के जवाब में भी सत्तापक्ष की ओर से रोजगार सहित विभिन्न मुद्दों पर आंकड़ों की बात नहीं की गयी। उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की तर्ज पर प्राक्कल समिति को भी निष्क्रिय बनाने का आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार सिर्फ अकड़ की बात करती हैं, आंकड़ों की नहीं।

न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को किया निरस्त

कोरेगांव-भीमा हिंसा मामला

नयी दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें उसने महाराष्ट्र पुलिस को कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने हालांकि यह भी कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपपत्र दायर कर दिया है इसलिए मामले में गिरफ्तार किए गए पांच कार्यकर्ता अब नियमित जमानत की मांग कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पहले बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें उसने मामले में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया था। निचली अदालत ने राज्य पुलिस को मामले में आरोपपत्र दायर करने की अवधि में 90 दिन का विस्तार दे दिया था। मामले में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं ने आरोप

लगाया था कि वे कानूनी रूप से जमानत के हकदार हैं क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने निर्धारित 90 दिन और उसके बाद भी आरोपपत्र दायर नहीं किया। ऐसी स्थिति में निचली अदालत द्वारा समय सीमा बढ़ाना कानूनी दृष्टि से सही नहीं था। गौरलतब है कि पुणे पुलिस ने माओवादी से कथित संबंधों के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराओं के तहत वकील सुरेंद्र गडलिंग, नागुपर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शोमा सेन, दलित कार्यकर्ता सुधीर धावले, कार्यकर्ता महेश राउत और केरल के रोना विल्सन को जून में गिरफ्तार किया था।

400 साल पुराना लाखों का बोनसाई पेड़ हुआ चोरी

एजेंसी। जापान की राजधानी टोक्यो के करीब स्थित सैमाता प्रांत से सात बोन्साई पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। इनमें 400 साल पुराना शिम्पाकु पेड़ भी शामिल है। इसे बोन्साई दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इन सभी पेड़ों की कीमत 83.78 लाख रुपए (118000 डॉलर) बताई जा रही है।शिम्पाकु अकेले की कीमत ही 64 लाख रुपए (90,000 डॉलर) से ज्यादा है। बोन्साई के क्षेत्र में काम करने वाली फ्युमी लिमुरा बताती हैं कि वे इन छोटे-छोटे पेड़ों को बच्चे की तरह पालती हैं। उन्होंने चोरों से अपील की है कि वे नियमित रूप से उन्हें पानी देते रहें। उनका कहना है कि बिना पानी के बोनसाई एक हफ्ते भी नहीं बच पाएंगे।

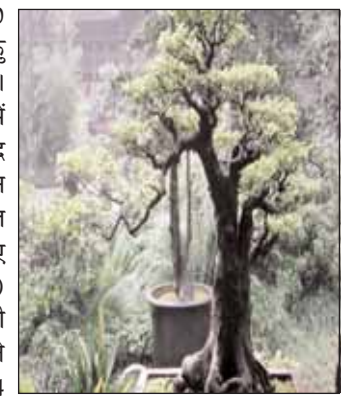

वे बताती हैं कि इन्हें चुराने वाले लोग आम नहीं बल्कि पेशेवर थे। वे जानते थे कि 5000 हेक्टर में लगे 3000 बोन्साई पेड़ों में से किसे चुराना है। जिन पेड़ों को चुराया गया है कि उनमें तीन छोटे देवदार के पेड़ थे, जिन्हें गोयोमैटस कहा जाता है। इसके अलावा, कम कीमत के तीन शिम्पाकु जूनिपर पेड़ शामिल हैं। जूनिपर बेहद दुर्लभ पेड़ है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 13 फरवरी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मीडिया इकाइयों का पहला सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ करेंगे।

सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न मीडिया इकाइयों के अंतर्गत कार्य कर रहे भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय स्तर पर एक स्थान पर लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां वे उभरते हुए संचार प्रतिमानों के बारे में चर्चा कर सकें। इस सम्मेलन के जरिए मंत्रालय का उद्देश्य मीडिया इकाइयों के बीच मिलकर कार्य करने की भावना को मजबूत करना है, ताकि अंतिम मील तक जानकारी पहुंचाई जा सके। सम्मेलन में इसके अलावा संचार में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में भी चर्चा होगी।

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि लक्षित श्रोता समूहों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे और भौगोलिक तथा सांस्कृतिक बाधाओं के सम्बन्ध में संचार की पहुंच को बढ़ाने के बारे में भी बातचीत करेंगे।